

[2008] 7 एस. सी. आर 752

आयकर आयुक्त, तिरुवनंतपुरम

बनाम

जोसेफ वालाकुझी

(सिविल अपील सं. 7750/2002)

6 मई, 2008

■अशोक भान और दलवीर भान्डारी, जे. जे.■

न्यायालय का निर्णय भान, न्यायाधीश

1. न्यायालय की अनुमति से राजस्व ने आईटीए नंबर 105/1999 में केरल उच्च न्यायालय के 27 नवंबर, 2001 के फैसले और आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 260 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. प्रतिवादी-निर्धारिती (संक्षेप में "निर्धारिती") एक फिल्म निर्माता है। निर्धारण वर्ष 1992-93 के लिए अपने आयकर रिटर्न में, निर्धारिती ने परिशोधन व्यय के रूप में रु. 39,43,830/- को आगे बढ़ाने के लाभ का दावा किया। निर्धारण अधिकारी ने परिशोधन के दावे की अनुमति दी। अपील पर, आयकर आयुक्त ने अधिनियम की धारा 263 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, मूल्यांकन को रद्द कर दिया और मूल्यांकन अधिकारी को इस आधार पर निर्धारिती को दिए गए कैरी फॉरवर्ड के लाभ को वापस लेने का निर्देश दिया। अधिनियम की धारा 80 लागू है, खर्चों को आगे बढ़ाने का लाभ निर्धारिती को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारिती अधिनियम की धारा 139(3) के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा था। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के समक्ष उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई।

3. इसके बाद, मूल्यांकन अधिकारी ने धारा 143(3) के तहत एक नया आदेश पारित करके आयकर आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों को लागू किया, जिससे निर्धारिती को दिए गए परिशोधन व्यय को आगे बढ़ाने का लाभ वापस ले लिया गया। व्यथित होकर निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की। सीआईटी (अपील) ने अपील स्वीकार कर ली। यह पाया गया कि आगे बढ़ाए जाने वाले परिशोधन व्यय की गणना, जैसा कि निर्धारिती द्वारा दिखाया गया था, सही नहीं थी। निर्धारिती ने दो फिल्मों के संबंध में परिशोधन व्यय का दावा किया था, अर्थात्, (i) पूर्व कन्निककोडी और (ii) संथवनम। ऐसा प्रतीत होता है कि पहली फिल्म में करदाता को भारी नुकसान हुआ और उस नुकसान की भरपाई के लिए करदाता ने दूसरी फिल्म का निर्माण करने का साहस किया। आयकर नियमों का नियम 9 ए (संक्षेप में "नियम") फीचर फिल्मों के निर्माण पर किए गए व्यय के संबंध में कटौती का प्रावधान करता है। यह पाए जाने पर कि निर्धारिती द्वारा दिखाए गए अनुसार आगे ले जाने के लिए परिशोधन व्यय की गणना सही नहीं थी, सीआईटी (अपील) ने मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारिती द्वारा निर्मित विभिन्न फिल्मों के संबंध में अलग-अलग खाते प्राप्त करने और दावे का निर्धारण करने के निर्देश दिए। नियमों के नियम 9 ए के अनुसार परिशोधन। यह स्पष्ट किया गया था कि यदि ऐसी गणना पर पुरानी फिल्म के संबंध में नुकसान होता है, तो उसे अधिनियम की धारा 139(3) और 80 के प्रावधानों के अधीन होना होगा। दूसरे शब्दों में, यह माना गया कि पुरानी फिल्मों के संबंध में यदि हानि होती है, तो वह केवल तभी आगे बढ़ाने के लिए पात्र होगी यदि आय का रिटर्न वैधानिक अवधि के भीतर दाखिल किया गया हो। दूसरी फिल्म के संबंध में, यह माना गया कि अगले वर्ष के लिए परिशोधन भत्ता अधिनियम की धारा 80 और धारा 139(3) के प्रावधानों के अधीन नहीं था। अपीलीय प्राधिकारी का यह निष्कर्ष था कि दूसरे वर्ष से संबंधित परिशोधन व्यय को अगले वर्ष की आय की गणना करते समय अलग से अनुमति देनी होगी, न कि चालू वर्ष की आय की गणना के समय। सीआईटी (अपील) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ व्यथित होकर, राजस्व ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की, जिसे कुछ स्पष्टीकरणों के साथ खारिज कर दिया गया।

4. इसके बाद राजस्व ने अधिनियम की धारा 260 के तहत उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने अपने विचार के लिए उक्त अपील में कानून के

निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए:

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर नियम 9 ए के तहत गणना की गई परिशोधन हानि आयकर अधिनियम की धारा 80 और धारा 139 के प्रावधानों के अधीन है या नहीं?"

5. अधिनियम की धारा 80 के तहत प्रदान किए गए व्यावसायिक नुकसान को आगे बढ़ाने और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए आय से अधिक व्यय को आगे बढ़ाने के बीच अंतर करना, जिसमें फिल्म 180 दिनों से अधिक समय तक प्रदर्शित नहीं की गई थी। नियमों के नियम 9 ए(3) के तहत प्रावधानित, यह माना गया कि वर्तमान मामला नियमों के नियम 9 ए(3) के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, न कि अधिनियम की धारा 80 द्वारा। यह पाया गया कि निर्धारिती द्वारा निर्मित दूसरी फिल्म पिछले वर्ष के दौरान 180 दिनों तक प्रदर्शित नहीं की गई थी, इसलिए निर्धारिती अगले मूल्यांकन वर्ष में व्यावसायिक व्यय को आगे बढ़ाने का हकदार था।

6. धारा 80 को अध्याय VI में अपना स्थान मिलता है जो आय के एकत्रीकरण और हानि को आगे ले जाकर समायोजित करने से संबंधित है, जो प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के दौरान प्रचलित है, इस प्रकार पढ़ें: "धारा 80 हानि के लिए रिटर्न जमा करना इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी हानि जो धारा 139 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार दाखिल रिटर्न के अनुसरण में निर्धारित नहीं की गई है, उसे उपधारा (1) के तहत आगे बढ़ाया और समायोजित किया जाएगा। धारा 72 या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74 ए की उपधारा (3)।

7. प्रासंगिक समय में धारा 80 में प्रावधान है कि धारा 139 की उप-धारा (3) के तहत दायर रिटर्न के अनुसरण में कोई भी हानि निर्धारित नहीं की गई है, जिसे धारा की उप-धारा (1) के तहत आगे बढ़ाया और समायोजित किया जा सकता है। 72 या धारा 73 की उपधारा (2) या धारा 74 की उपधारा (1) या उपधारा (3) या धारा 74 ए की उपधारा (3)

8. जाहिर है, अध्याय VI व्यावसायिक घाटे को आगे बढ़ाने से संबंधित है।

9. नियमों का नियम 9 ए, जो प्रासंगिक समय पर फीचर फिल्मों (जो एक विशेष

प्रावधान है) के निर्माण पर व्यय की कटौती से संबंधित है, इस प्रकार पढ़ें: "9 ए। फीचर फिल्मों के निर्माण पर व्यय के संबंध में कटौती।

(1) किसी व्यक्ति (इसके बाद इस नियम में ऐसा व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को फिल्म निर्माता कहा गया है) द्वारा किए गए फीचर फिल्मों के उत्पादन के व्यवसाय के मुनाफे और लाभ की गणना करने में, उत्पादन की लागत के संबंध में कटौती पिछले वर्ष फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज के लिए प्रमाणित फीचर फिल्म को उप-नियम (2) से उप-नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी,

स्पष्टीकरण: इस नियम में, -

(i) "फिल्म सेंसर बोर्ड" का अर्थ सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के तहत गठित फिल्म सेंसर बोर्ड है;

(ii) फीचर फिल्म के संबंध में "उत्पादन की लागत" का अर्थ फिल्म के निर्माण पर किया गया व्यय है, न कि- (ए) फिल्म के सकारात्मक प्रिंट की तैयारी के लिए किया गया व्यय; और (बी) फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज के लिए प्रमाणित होने के बाद फिल्म के विज्ञापन के संबंध में किया गया व्यय: बशर्ते कि एक फीचर फिल्म के निर्माण की लागत, फिल्म निर्माता द्वारा प्राप्त सब्सिडी से कम हो जाएगी सरकार द्वारा बनाई गई कोई भी योजना, जहां किसी भी मूल्यांकन वर्ष के लिए निर्धारित की कुल आय की गणना में सब्सिडी की ऐसी राशि शामिल नहीं की गई है।

(2) जहां किसी फीचर फिल्म को किसी पिछले वर्ष और ऐसे पिछले वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज के लिए प्रमाणित किया जाता है, -(ए) फिल्म निर्माता फिल्म के प्रदर्शन के सभी अधिकार बेचता है, फिल्म के उत्पादन की पूरी लागत को ऐसे पिछले वर्ष के मुनाफे और लाभ की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी; या (बी) फिल्म निर्माता--(i) स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है; या (ii) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या (iii) स्वयं कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है, और फिल्म को कम से कम एक सौ और व्यावसायिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी किया जाता है।

ऐसे पिछले वर्ष के अंत से अस्सी दिन पहले, फिल्म के उत्पादन की पूरी लागत को ऐसे पिछले वर्ष के मुनाफे और लाभ की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

(3) जहां किसी फीचर फिल्म को किसी पिछले वर्ष में फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा रिलीज के लिए प्रमाणित किया जाता है और ऐसे पिछले वर्ष में, फिल्म निर्माता (ए) स्वयं सभी या कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है; या (बी) कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है; या (सी) स्वयं कुछ क्षेत्रों में व्यावसायिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करता है और शेष सभी या कुछ क्षेत्रों के संबंध में फिल्म के प्रदर्शन के अधिकार बेचता है, और फिल्म को कम से कम एक सौ क्षेत्रों में व्यावसायिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी नहीं किया जाता है। और ऐसे पिछले वर्ष के अंत से अस्सी दिन पहले, फिल्म के उत्पादन की लागत जहां तक यह फिल्म निर्माता द्वारा व्यावसायिक आधार पर फिल्म का प्रदर्शन करके प्राप्त की गई राशि या उस राशि से अधिक न हो जिसके लिए प्रदर्शन का अधिकार है बेचे जाते हैं या, जैसा भी मामला हो, फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म प्रदर्शित करके और प्रदर्शनी के अधिकारों की बिक्री से प्राप्त कुल राशि को ऐसे पिछले वर्ष के मुनाफे और लाभ की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी; और शेष, यदि कोई हो, अगले अगले पिछले वर्ष में ले जाया जाएगा और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

(4) ..."

10. पक्षों के वकील को सुना गया है।

11. हमारे सामने यह विवादित नहीं है कि एक फिल्म एक फिल्म निर्माता के हाथ में एक पूंजीगत संपत्ति है और राज्य सरकार द्वारा एक फिल्म निर्माता को दी जाने वाली सब्सिडी एक पूंजीगत प्राप्ति है। धारा 80 अध्याय VI के अंतर्गत आती है, जो आय के एकत्रीकरण और हानि के समायोजन या आगे ले जाने से संबंधित है।

12. नियम 9ए फीचर फिल्मों के निर्माण पर होने वाले व्यय में कटौती का प्रावधान करता है। नियम 9ए वर्तमान मामले पर उचित रूप से लागू होगा, क्योंकि प्रतिवादी फीचर फिल्मों के निर्माण का व्यवसाय कर रहा है। फीचर फिल्मों के निर्माण पर किए गए व्यय की कटौती नियमों के नियम 9ए द्वारा उचित रूप से नियंत्रित होती है।

13. नियम, जैसा कि अब है, प्रावधान करता है कि ऐसे मामलों में, फिल्म के

उत्पादन की लागत में कटौती उस वर्ष वाणिज्यिक प्रदर्शन के दिनों की संख्या के दौरान प्राप्त राशि और शेष राशि की सीमा तक की अनुमति दी जानी है। अगले वर्ष में अनुमति देनी होगी। नियम 9 ए(2) में प्रावधान है कि जहां एक फीचर फिल्म को किसी पिछले वर्ष में रिलीज के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है, और उस पिछले वर्ष में फिल्म को उस पिछले वर्ष के अंत से पहले कम से कम 180 दिनों के लिए प्रदर्शन के लिए जारी किया जाता है, , फिल्म के उत्पादन की पूरी लागत को ऐसे पिछले वर्ष के मुनाफे और लाभ की गणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। नियम 9 ए(3) में प्रावधान है कि जहां फिल्म पिछले वर्ष 180 दिनों तक प्रदर्शन के लिए जारी नहीं की गई है, उस वर्ष वाणिज्यिक प्रदर्शन की अवधि के दौरान प्राप्त राशि की सीमा तक उत्पादन लागत में कटौती की अनुमति दी जाएगी और शेष राशि अगले वर्ष में स्वीकृत की जाएगी।

14. माना जाता है कि, वर्तमान मामले में, दूसरी फिल्म, अर्थात् "संथवनम" पिछले वर्ष में 180 दिनों से अधिक समय तक प्रदर्शित नहीं की गई थी। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष 1992-93 के लिए आय या हानि की गणना करते समय, मूल्यांकन अधिकारी को उन दिनों की संख्या को ध्यान में रखना था जिन दिनों फिल्म का व्यावसायिक प्रदर्शन किया गया था और फिर फिल्म के उत्पादन की लागत के लिए कटौती की अनुमति दी गई थी। केवल प्रदर्शनी की अवधि के दौरान किए गए संग्रह। उत्पादन की शेष लागत नियम 9 ए(2) के तहत परिशोधित की जाएगी और फिर उसे अगले वर्ष के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यह कोई व्यापारिक घाटा नहीं है। यदि किसी फिल्म को पिछले वर्ष की समाप्ति से कम से कम 180 दिन पहले व्यावसायिक आधार पर प्रदर्शन के लिए जारी नहीं किया जाता है, तो फिल्म के निर्माण की लागत उस हद तक नहीं होती है जब वह फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म का प्रदर्शन करके प्राप्त की गई राशि से अधिक न हो। वाणिज्यिक आधार पर, ऐसे पिछले वर्ष के लाभ और लाभ की गणना में कटौती की अनुमति दी जानी है और शेष राशि, यदि कोई हो, को अगले पिछले वर्ष में आगे बढ़ाया जाना है और उस वर्ष में कटौती के रूप में अनुमति दी जानी है। बेशक, वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दूसरी फिल्म "संथवनम" पिछले वर्ष 180 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित नहीं की गई थी, और, फिल्म के उत्पादन की लागत को कवर नहीं किया था, निर्धारित आगे बढ़ने का हकदार था अगले पिछले वर्ष के लिए उत्पादन लागत का शेष और उस वर्ष में उसी की

कटौती का दावा करें।

15. ऊपर बताए गए कारणों से, हम वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और इसे खारिज करते हुए पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी तेजकिरन कौर चावला (आर.जे.एस.), द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।